के आधार पर भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण शुरू किया गया था। बाद में प्रायोगिक परियोजनाओं की संख्या बढ़ाकर 21 करते हुए इसे 13 और जिलों में शुरू किया गया था। प्रायोगिक परियोजनाओं के उत्साहवर्धक परिणामों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अब एक अलग केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभी तक देश के 99 जिलों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया गया है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 24.28 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान कुछ और जिलों को शामिल किया जाएगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश को कवर कर पाना सम्भव नहीं होगा। चूंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना का कार्यान्वयन नौवीं पंचवर्षीय योजना में योजना की स्थिति पर निर्भर करेगा, यह बता पाना सम्भव नहीं है कि इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के लिए राशि का आवंटन

2697. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को ग्रामीण स्वच्छता के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) इस अवधि के दौरान और अब तक इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण स्वच्छता हेतु उत्तर प्रदेश को आबंटित की गई धनराशि एवं इस संबंध उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

(लाख रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यलय के अंतर्गत आबंटित निधिया	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता क्रम के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियां	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचित खर्च	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित खर्च	निर्मित किए गए शौचालयों की संख्या
1991-92	530.400	1100.00	0.00*	1594.45	98.000	1594.45	88005
1992-93	261.09	1519.00	267.890	1519.00	शून्य	1095.94	69590
1993-94	391.438	801.00	491.438	800.99	659.32	774.99	48335
1994-95	785.000	2784.00	587.25**	200.00	391.00	793.37	36679
							(अक्तूबर, 1994 तक)

*1991-92 के दौरान योजना का अनुमोदन न होने के कारण किसी भी राज्य को केन्द्रीय सहायता रिलीज नहीं की गई थी।

**अभी तक 75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा चुकी है। बकाया केन्द्रीय सहायता यथा समय पर रिलीज की जाएगी।

'Gurudaspur Plan'

2698. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that during disturbances in Punjab, a special project was got prepared by Punjab State Khadi and Village Industries Board to help the rural unemployed youth of Gurudaspur district during 1986 in the name of 'Gurudaspur Plan' ;

(b) whether it is also a fact that on the basis of this plan, an amount of about Rs. 10 crore was sanctioned by the Ministry of Industry to be routed through Khadi and Village Industries Commission;

(c) if so, how many units were supposed to be financed during 1986-90 as per the plan as compared to actually financed units during that period;

(d) whether this plan continued upto March, 1990; and

(e) if not, when and which authority suspended/surrendered the above mentioned Gurudaspur Plan and the reasons for such action ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. It has, however, been reported by Khadi and Village Industries Commission (KVIC) that funds were allotted to the Punjab State KVI Board by the KVIC on its own for implementation of special programme Gurudaspur district as under :

(Rs. in lakhs)

Year	Funds allotted
1986-87	36.86
1987-88	71.76
1988-89	51.94
1989-90	18.41

(c) to (e) KVIC decided to set up more that 6000 units under 13 village industries in Gurudaspur during the period 1986-87 1987-88, 1988-89 and 1989-90 with a financial outlay of Rs. 9.13 crores. The programme was not pursued beyond 1990 since the Punjab KVI Board did not ask for any specific sanction from the KVIC beyond 1990.

Funds allotted to Punjab for Rural Development

2699. SHRI IQBAL SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the total amount allotted to the State of Punjab under different rural development schemes; and

(b) the amount actually utilised out of the same so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) (a) and (b) Integrated Rural Development Programme (IRDP), Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Accelerated Rural Water Supply Scheme (ARWSP) are the major rural development schemes being implemented by the Central Government in the state of Punjab. The total amount allocated under the above schemes during 1994-95 to the state of Punjab and corresponding utilisation are as follows :—

(Rs. in lakhs)

Scheme	Total Allocation during 1994-95	Actual utilisation
I.R.D.P.	523.00	339.28 (upto Oct. 94)
J.R.Y.	1,699.28	210. (upto August. 94)
A.R.W.S.P.	775.00	420.74 (upto Oct. 94)

IRWE Project from Gujarat for World Bank Assistance

2700. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government of Gujarat has sent any Integrated Rural Water Supply and Environmental Project for the World Bank assistance;

(b) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon;

(c) the estimated cost of this project; and

(d) the number of villages likely to be covered under the proposed scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

बिहार के बांका जिले के लिए सघन योजना

2701. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार का बांका जिला पिछड़ा जिला है ;